



22 मई 2023

## डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

### सन्दर्भ:

- केंद्र सरकार इस साल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना और मालिकाना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विकल्प की पेशकश करना है।

### ओएनडीसी क्या है?

- सरकार ई-कॉमर्स बाजार की मूलभूत संरचना को मौजूदा "प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक ओपन-नेटवर्क मॉडल" में बदलना चाहती है।
- ONDC को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रोजेक्ट के बाद तैयार किया गया है, जिसे कई लोग सफलता के रूप में देखते हैं।
- यूपीआई परियोजना लोगों को पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देती है चाहे वे किसी भी भुगतान प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों।
- इसी तरह सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ई-कॉमर्स बाजार में सामान के खरीदार और विक्रेता उन प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिए बिना लेनदेन कर सकते हैं जिन पर वे पंजीकृत हैं।
- उदाहरण के लिए ओएनडीसी के तहत, अमेज़ॉन पर पंजीकृत एक खरीदार सीधे फ्लिपकार्ट पर बेचने वाले विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
- इस तरह के लेनदेन को वास्तविकता बनाने के लिए सरकार ने कंपनियों को ओएनडीसी पर खुद को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

### सरकार इसके लिए जोर क्यों दे रहा है?

- वर्चस्व खत्म:** सरकार का मानना है कि ओएनडीसी कुछ बड़े प्लेटफॉर्मों द्वारा ई-कॉमर्स बाजार के वर्चस्व को समाप्त कर देगा।
- इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स बाजार वर्तमान में "साइलो" में बंटा हुआ है जो निजी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है।
- उदाहरण के लिए Amazon और Flipkart पर कुछ विक्रेता संस्थाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उनकी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है।

### महत्व:

- ओएनडीसी एक जैसे खुले नेटवर्क के साथ (जो खरीदारों और विक्रेताओं को प्लेटफॉर्मों में जोड़ता है) सरकार इसको समतल करने और निजी प्लेटफॉर्मों को बेमानी बनाने की उम्मीद करती है।

## जिओ-टैगड नालियां

### Face to Face Centres





22 मई 2023

## सन्दर्भ:

- गंगा नदी के तट पर स्थित सभी गांव से निकलने वाले सभी नालों की 'जियो टैगिंग' की जायेगी। ताकि कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोका जा सके।

## मुख्य विशेषताएं:

- तत्काल कार्रवाई करने के लिए जियो-टैग किए गए नालों के बारे में जानकारी शहरी स्थानीय निकायों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन (जी) के साथ साझा की जाएगी।
- उत्तरकाशी (उत्तराखंड) में एक सुरंग के निर्माण के कारण गंगा नदी के किनारों पर मलबा डाला जा रहा है, जिससे नदी के पानी में ठोस अपशिष्ट प्रदूषण में वृद्धि हुई है।
- गंगा नदी के किनारे विभिन्न स्थानों पर ठोस अपशिष्ट डाला जा रहा है, जो नदी के पानी में जमा हो रहा है।
- नदी के पानी में ठोस अपशिष्ट की उपस्थिति सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) में अपशिष्ट जल के उपचार में कठिनाइयों का कारण बन रही है।
- जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने स्क्रीन लगाने और नदी के पानी में ठोस कचरे को जाने से रोकने के लिए अमृत 2.0 से धन का उपयोग करने का सुझाव दिया।

## जियोटैगिंग क्या है?

- जियो-टैगिंग भौगोलिक मेटाडेटा (जैसे कि निर्देशांक या स्थान की जानकारी) मीडिया के विभिन्न रूपों जिसमें फोटोग्राफ, वीडियो या शाब्दिक डेटा शामिल हैं, को जोड़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- यह मीडिया सामग्री के साथ एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान की सटीक पहचान और जुड़ाव को सक्षम बनाता है।
- भू-टैगिंग किसी विशेष बिंदु के सटीक निर्देशांक निर्धारित करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तकनीक या अन्य स्थान-आधारित सेवाओं का उपयोग करती है।
- इन निर्देशांकों को तब एम्बेड किया जाता है या मीडिया से जोड़ा जाता है, जिससे इसे भौगोलिक रूप से संदर्भित किया जा सके।

## रक्षा उत्पादन

## सन्दर्भ:

- भारत ने घोषणा की है कि देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार ₹1 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है।

Face to Face Centres



22 मई 2023

## मुख्य विशेषताएं:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य ₹ 1,06,800 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष ₹ 95,000 करोड़ और पांच साल पहले ₹ 54,951 करोड़ था।
- भारत ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर निम्न उपायों को लागू कर रहा है:
  - आयात प्रतिबंध।
  - घरेलू खरीद के लिए एक अलग बजट।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि।
  - व्यापार करने में आसानी।
- सरकार की नीतियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप सहित उद्योगों की भागीदारी में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2021 में आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण ने भी रक्षा उत्पादन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योगदान दिया है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में सैन्य हार्डवेयर निर्यात ₹15,920 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ भारत का ध्यान रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
- भारत कई देशों को हथियारों और प्रणालियों की एक श्रृंखला का निर्यात कर रहा है, जिसमें मिसाइल, तोपखाने की बंदूकें, रॉकेट, वाहन, रडार, निगरानी प्रणाली और गोला-बारूद शामिल हैं।



## मेथामफेटामाइन (Methamphetamine)

### सन्दर्भ:

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारतीय नौसेना ने केरल तट पर एक संयुक्त अभियान चलाया।
- इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग ₹15,000 करोड़ मूल्य का 2,500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया गया।

### Face to Face Centres



22 मई 2023

**मुख्य विशेषताएं:**

- मेथामफेटामाइन (जिसे आमतौर पर मेथ के रूप में जाना जाता है) एक अत्यधिक नशे की लत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक दवा है।
- यह दवाओं के एम्फैटेमिन वर्ग से संबंधित है और रासायनिक रूप से एम्फैटेमिन के समान है।
- मेथामफेटामाइन आमतौर पर अवैध प्रयोगशालाओं में निर्मित होता है और एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में आता है जिसे सूंघा, धूम्रपान, इंजेक्शन या मौखिक रूप से लिया जा सकता है।
- भारत में किसी भी दवा-विरोधी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मौद्रिक मूल्य के मामले में इस दवा की जब्ती अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है।
- नशीले पदार्थों की उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई थी जिन्हें मकरान तट से एक मदर शिप पर लादा गया था। यह अभियान 'ऑपरेशन समुद्रगुप्त' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करना है।



**संक्षिप्तसुर्खियां**

**वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली**

**सन्दर्भ:**

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली (डब्ल्यूएडी) को 232 जल निकायों को हटाने का अनुरोध किया है, जो इसके रिकॉर्ड में कुल 1,045 जल निकायों का 22.2% है।

**मुख्य विशेषताएं:**

**Face to Face Centres**



**22 मई 2023**



- अतिक्रमण या सूखने जैसे कारणों का हवाला देते हुए शहर में जल निकायों के स्वामित्व वाली 16 एजेंसियों में से कुछ ने हटाने के अनुरोध किए हैं।
- डब्ल्यूएडी ने 710 जल निकायों के लिए "संक्षिप्त दस्तावेज" तैयार किए हैं, जबकि बाकी पर या तो कब्जा कर लिया गया है या उनके मालिकों की पहचान की जानी बाकी है।
- 1997 के एक सर्वेक्षण में 1,000 से अधिक जलाशयों और वर्तमान संख्या 700 से कम होने के संकेत के साथ, दिल्ली में जल निकायों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी कमी आई है।
- उदाहरण के लिए नजफगढ़ झील 1883 में 80 वर्ग किमी से घटकर वर्तमान में केवल 5 वर्ग किमी रह गई है।
- आर्द्रभूमियाँ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:
  - विविध पौधे और पशु जीवन का समर्थन करना,
  - शहरी बाढ़ को कम करना,
  - पानी को शुद्ध करना और भंडारण करना,
  - भूजल पुनर्भरण,
  - क्षरण को नियंत्रित करना,
  - माइक्रोकलाइमेट को विनियमित करना।

## व्लादिवोस्तोक बंदरगाह

### सन्दर्भ:

- चीन और रूस आर्थिक सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते में शामिल हुए हैं।

### मुख्य विशेषताएं:

- यह समझौता व्लादिवोस्तोक के रूसी बंदरगाह को चीन से घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में उपयोग करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और पूर्वोत्तर चीन के औद्योगिक आधार के पुनरोद्धार का समर्थन करना है।
- चीन ने परिवहन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लागत को कम करने के लिए व्लादिवोस्तोक को अपने घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में नामित किया



### Face to Face Centres





**22 मई 2023**

है।

- यह समझौता चीन को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र से झेजियांग प्रांत तक माल की दुलाई के लिए एक छोटा और कम लागत प्रभावी मार्ग प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में काफी बचत होती है।
- यह समझौता जून 2023 में प्रभावी होने के लिए निर्धारित है, व्लादिवोस्तोक को जिलिन प्रांत के लिए एक घरेलू बंदरगाह के रूप में स्थापित करना और टैरिफ या करों के बिना माल के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करना भी इसमें शामिल है।
- यह व्यवस्था पूर्वोत्तर चीन में अपने औद्योगिक आधार को पुनर्जीवित करने, सीमा पार व्यापार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और चीन और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने की चीन की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के अनुरूप है।
- प्रिमोस्की क्राय क्षेत्र में स्थित व्लादिवोस्तोक, प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है और चीन-रूस सीमा से लगभग 45 किलोमीटर दूर गोल्डन हॉर्न बे के आसपास रणनीतिक रूप से स्थित है।

## पैच रिपोर्टिंग ऐप

**सन्दर्भ:**

- हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों पर गड्डों के मुद्दे को हल करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित "पैच रिपोर्टिंग ऐप" का उद्घाटन किया।

**मुख्य विशेषताएं:**

- उपयोगकर्ता के अनुकूल यह ऐप लोगों को गड्डों की रिपोर्ट करने और उत्तराखंड की सड़कों को सुरक्षित और गड्डा मुक्त बनाने के लिए की गई कार्रवाइयों की निगरानी करने के लिए है।
- यह ऐप नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने और गड्डों की तस्वीरों सहित विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करके जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाता है।
- यह दृश्य साक्ष्य के साथ शिकायतों को हल करने के लिए की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट देकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- इस ऐप में एक इंटरैक्टिव और स्थान-आधारित डिज़ाइन है जो लोक निर्माण विभाग



**Face to Face Centres**



**22 मई 2023**

द्वारा त्वरित कार्रवाई को सक्षम करने के लिए अक्षांश और देशांतर निर्देशांक का उपयोग करके सटीक स्थान की जानकारी प्रदर्शित करता है।

- इसमें शिकायतकर्ताओं और उच्च पद के अधिकारियों दोनों को किए गए कार्य का व्यापक विवरण प्राप्त होता है, जिसके साथ फोटोग्राफ भी होते हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

### महत्व:

- पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्देश्य सड़क बुनियादी ढांचे के रखरखाव में नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करके सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- यह उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित सड़कों पर गड्डों की सूचना देने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में कार्य करता है।

### गगनयान

### सन्दर्भ:

- भारत के गगनयान कार्यक्रम हेतु फिटमेंट टेस्ट से गुजरने के लिए स्वदेशी रूप से पैराशूट विकसित हो गया।

### मुख्य विशेषताएं:

- इन पैराशूटों को गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले कैप्सूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए पैराशूट का फिटमेंट परीक्षण बेंगलुरु में किया जाएगा।
- पैराशूट प्रणाली में 10 पैराशूट होते हैं, जो प्रत्येक क्रू मॉड्यूल के उतरने के दौरान एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए काम करता है।
- तैनाती के क्रम में एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट, स्थिरीकरण के लिए ड्रग पैराशूट, निष्कर्षण के लिए पायलट पैराशूट और सुरक्षित लैंडिंग के लिए मुख्य पैराशूट शामिल हैं।

### महत्व:

- ऐसे प्रदर्शनों की सफलता मानव रहित मिशन के लिए तैयारी का निर्धारण करेगी। परीक्षण वाहन प्रदर्शन (TVD-1) उड़ान भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम



### Face to Face Centres



**22 मई 2023**

की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

**कैल्शियम-41**



**सन्दर्भ:**

- रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिये कैल्शियम-41 का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।

**मुख्य विशेषताएं:**

- कैल्शियम-41 की अर्ध-आयु लगभग  $1.04 \times 10^5$  वर्ष है, जो कार्बन-14 (5730 वर्ष) की अर्ध-आयु से काफी अधिक है।
- इसका आधा जीवन कैल्शियम -41 को पिछले कुछ लाख वर्षों के भीतर हुई भूगर्भीय घटनाओं के डेटिंग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकि कार्बन -14 लगभग 50,000 वर्ष पुरानी डेटिंग सामग्री तक सीमित है।
- कैल्शियम-41 के नाभिक में 20 प्रोटॉन और 21 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे इसकी द्रव्यमान संख्या 41 हो जाती है।
- कैल्शियम-41 के वितरण और संचलन का अध्ययन करके शोधकर्ता विभिन्न प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि जैसे कि हड्डी निर्माण, कैल्शियम परिवहन, और समुद्री और स्थलीय प्रणालियों में कैल्शियम की गतिशीलता प्राप्त कर सकते हैं।

**अनुच्छेद 239AA**



**सन्दर्भ:**

- राजधानी दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर अधिकार सहित दिल्ली के उपराज्यपाल को विस्तारित शक्तियां प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया।

**मुख्य विशेषताएं:**

- इस अध्यादेश का उद्देश्य सीजेआई डी वाई चंद्रचूड के नेतृत्व वाली संविधान पीठ के फैसले के प्रभाव को कम करना है, जिसने दिल्ली सरकार को राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था।

**संविधान का अनुच्छेद 239AA क्या है?**

- अनुच्छेद 239AA 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसने एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान

**Face to Face Centres**





**22 मई 2023**

किया। इस प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधानसभा होगी।

- पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर दिल्ली की विधानसभा को इसके लिए कानून बनाने का अधिकार है।

### सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

- 2018 में बहुमत के फैसले में अदालत ने कहा कि संघवाद की अवधारणा अभी भी इस पर लागू होती है इसलिए दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
- अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 239AA दिल्ली के लिए सरकार हेतु प्रतिनिधि रूप के लिए प्रदान करता है, जिसमें राज्य और समवर्ती सूची के मामलों पर सीधे निर्वाचित विधान सभा और विधायी शक्तियाँ होती हैं।
- असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है, उपराज्यपाल (एलजी) को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

